NTC Losses

2077. PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the National Textile Corporation Limited has substantially reduced its losses by including the capital profit/revenue out of sales of some fixed assets of the Corporation;

(b) whether the loss during the period from January to June, 1989 has been slashed down to Rs. 118.81 crores from Rs. 143.17 crores during the corresponding period;

(c) if so, what are the details thereof; and

(d) what efforts are being made to adopt correct accounting procedure in ascertaining real profit or loss of the Corporation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (KUM. SAROJ KHAPARDE): (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) The month-wise details of the provisional net loss as reported by NTC Subsidiary Corporations are given below:

(Rs. in Crores)

	1988	1989
January . .	19.94	19.94
February . .	24.22	21.22
March . .	22.70	20.50
April . .	26.50	19.47
May . . .	26.46	18.82
June . . .	26.35	18.36
	143.17	118.31

(d) In view of reply to part (a) of the Question, question does not arise.

Violation of FERA Provisions

2078. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the officials of the Directorate of Enforcement, Bombay apprehended some persons for violating FERA provision during the last six months;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what action Government propose to take against the above persons?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO) : (a) to (c) During the last six months ending 30th June, 1989, officers of the Directorate of Enforcement at Bombay had arrested 60 persons. Out of these, 46 persons have since been released on bail. Two persons are continuing under judicial custody as they could not furnish bail bond, etc., as per orders of the court. Remaining 12 persons are in judicial custody as per orders of the court.

Appropriate action is taken against the offender as warranted under the law.

पंजाब नेशनल बैंक में अधिवक्ताओं के पैनल का बनाया जाना

2079. **श्री ईश दत्त यादव :**

श्री महेन्द्र सिंह लाठर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब नेशनल बैंक में अधिवक्ताओं के पैनल में हरिजनों, आदिवासियों अल्पसंख्यकों, पिछडे वर्गों और महिलाओं की संख्या क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन वर्गों को पैनल में समुचित प्रतिनियधित्व नहीं दिया गया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि जाति के आधार पर केवल एक विशेष वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी गई है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में जांच करने का विचार रखती है ; और

(ङ.) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फेलेरियो) : (क) से (ङ.) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण की वसूली

2080. **श्री ईश दत्त यादव :**

श्री महेन्द्र सिंह लाठर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ऋण के रूप में दिये गये धन की काफी बड़ी मात्रा को बट्टेखाते डालने की सिफारिश की गई है क्योंकि यह धन वसूली योग्य नहीं है, और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में वर्षवार कितना धन बट्टेखाते डाला गया है ; और

(ख) इस धन की वसूली न कर पाने के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फेलेरियो) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को नियंत्रित करने वाली सांविधियों तथा बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं और रीति-रिवाजों के अनुसार और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में निर्धारित तुलन पत्र एवं लाभ व हानि लेखे के फार्मेटों के अनुसार, जिनका बैंकों को पालन करना होता है, बैंक अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों की रकमें, जिनके वास्ते उनके सांविधिक लेखा परीक्षकों की तसल्ली के मुताबिक व्यवस्था कर ली गई हो तथा बट्टे खाते डाली गई अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों की रकमें प्रकट नहीं कर रहे हैं ।

बैंक अपनी प्राप्य रकमों की वसूली प्रतिभूतियों की उगाही एवं बिक्री, गारंटियों, की सहायता से तथा उपलब्ध बीमा कवच की उगाही के जरिए और संबंधित पार्टियों के खिलाफ सिविल मुकदमे दायर करके करते हैं । किसी भी ऋण को बटटे खाते डालने का निर्णय तभी लिया जाता है जब कानूनी अथवा बैंक के पास उपलब्ध अन्य उपाय विफल हो जाते हैं ।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि जहां कहीं भी यह पाया जाता है कि कोई अग्रिम उनके कर्मचारियों की लापरवाही, अक्षमता अथवा उधारकर्ताओं के साथ शंकास्पद साठगांठ के कारण अशोध्य हो गया है, तो सम्बंधित कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए । बैंक ऐसे अधिकारियों के खिलाफ उचित अनुशासनिक कार्रवाई करते हैं तथा यदि अपराध में शामिल होने की शंका होती है, तो मामले को आपराधिक जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा स्थानीय पुलिस को सौंप देते हैं ।

Reduction of Customs Duty on Drug Intermediates

2081. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that his Ministry has reduced customs duty on certan intermediates going into the production of bulk drugs and exemption of duty on certain drugs and finished medicines in order to givere llef to the public;

(b) whether it is also a fact that the consumers did not get any relief due to this reduction; and